IAS Mentorship

With Reyasat Ali sir & Experienced team in CSE prep

CSE Main 2023: Mini Mock Test 6

Syllabus:	• • Governance & Social Justice • •	
Name of Candidate	MOHAN MANGAWA	
Email Id		
Date		Medium: Hindi / English
Time: 1 Hour	Start Time:	End Time:

Q. No.	Max. Marks	Marks obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	15	
5	15	
6	15	
7	15	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total	90	
Invigilator	Signature	

WhatsApp/Telegram/Text/Call: 8090528260

Scanned with OKEN Scanner

	Excellent	Good	Average	Unsatisfied
Introduction				
Conceptual Understanding				
Contextual Clarity				
Content Enrichment				
Presentation				
Alignment				
Contextual Justification				

Scanned with OKEN Scanner

Q1. "It is necessary to reorient policy discourse to reflect social reality to lay foundation for a new social justice program". In the context of above statement analyze the pros and cons associated with caste census in Indian. 150 words

जॉन रोल्स के अनुसार सामाजिक न्याय एक निरंतर परिवर्तित होती प्रक्रिया है जो समय के साथ विभिन्न अवसरों को समाहित करने पर जोर देती है।

जाति विविधता व जातियों में बढ़ी हुआ सामाजिक-आर्थिक असमानता के कारण आजकल जाति आधारित जनगणना की मांग बढ़ी है जिसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव है-

सकारात्मक → जातिय पहचान → पॉलिसी निर्माण को आसान बनायेगी

↳ आरक्षण का तार्किकीकरण ⇒ इन्क्लूजन एक्सक्लूजन एरर कम होंगे

↳ पिछड़े क्षेत्रों तक लोककल्याण संभव
↳ योजनाओं का लाभ
↳ स्पष्ट पहचान संभव

↳ सरकार को स्पष्ट डेटा की प्राप्ति
↳ OBC के संबंध में अपर्याप्त डेटा

नकारात्मक → जातीय भावना को प्रबल → जातिवाद व समाज विघटन खतरा

↳ दलित जातियों के साथ शोषण होने की संभावना → जातीय प्रबलता व अधिकार प्राप्ति इच्छा के कारण

↳ OBC वर्गों में आरक्षण की मांग तीव्र होगी → जनसंख्या : आरक्षण अनुपात में बड़ा अन्तर के कारण

↳ जाति आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरण

जरूरत → जाति आधारित जनगणना करते हर सरकार द्वारा निष्पक्ष जाँच
↳ पिछड़े जातीय समूहों हेतु आरक्षण व उप-वर्गीकरण जैसी व्यवस्था
↳ क्षेत्र आधारित कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण।

इस प्रकार जाति भारतीय समाज का एक सत्य है अतः इस संबंध में पिछड़े जातीय समूहों को बेहतर अवसर प्रदान करने में जातिगत गणना उपयोगी साबित होगी।

Q2. Examine the potential benefits of Digitalization of Land records in India. 150 words

भूमि के डिजिटलीकरण का अर्थ है - भूमि रिकॉर्ड, मालिकी, क्षेत्र व इसके आकार का सम्पूर्ण डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध होना। इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं।

भू-डिजिटलीकरण की जरूरत

- भू-सुधार का प्रमुख अंग
  - सरकार के पास सटीक डाटा उपलब्धता
- गैर-कानूनी भूमि हस्तांतरण पर रोक
  - मुख्यतः SC-ST वर्ग के बीच
- स्थानीय बिचौलियों व जमींदारी वर्ग के प्रभुत्व कम करने में सहायता
- 85% सीमांत किसान → अतः FPOs व FPCs बनाकर चकबंदी प्रक्रिया को तीव्र करना

↳ सरकारी योजनाओं का तार्किककरण
↳ KCC व उर्वरक सब्सिडी को भू-डेटा से जोड़कर बेहतर किसान-सहायता

परन्तु समस्याएं → स्थानीय स्तर पर प्रमाणित डेटा की कमी → पटवारी, तहसीलदार के पास पुराना डेटा

↳ डिजिटल डिवाइड → केवल 37% डिजिटल साक्षरता (इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2024)

↳ जागरूकता अभाव व छोटी जोत के कारण उत्साह कम

↳ डिजिटलीकरण कार्यक्रमों का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वन मुश्किल → भौगोलिक, प्रशासनिक बाधाएं

जरूरत → स्थानीय स्वशासित निकायों के पटवारी-ग्राम सेवक के साथ मिलकर डाटा-अद्यतन कार्य

↳ 'भूमि' (KA) व SVAMITVA जैसी योजनाओं के प्रति जागरूकता

↳ KCC व अन्य सब्सिडी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल डाटा अनिवार्य करना → केरट एंड स्टिक सिद्धान्त

इस प्रकार एक बेहतर डाटा उपलब्धता देश की बड़ी जनसंख्या को बेहतर अवसर प्रदान करेगा साथ ही सरकार के भी राजकोष पर कम दबाव पड़ेगा।

Scanned with OKEN Scanner

Q3. "Human life, above all". In this context critically examine the pros and cons associated with Right to Health act passed in Rajasthan. Do you think this is a step towards achieving Health as a fundamental right at national level? 150 words

जीवन का अधिकार अनु० 21 के अनुसार मूलभूत व प्राकृतिक अधिकार है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनेका गांधी वाद (1978) में और अधिक विस्तृत प्रदान की गई।

इसी को आधार बनाकर राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य अधिकार का सार्वभौमिकरण किया गया जो एक सराहनीय कदम है-

- पिछड़े व गरीब जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा
- अच्छे अस्पतालों व आधुनिक स्वास्थ्य साधनों तक आम आदमी की पहुँच संभव
- #SDG लक्ष्यों 1, 2, 3 की प्राप्ति हेतु आवश्यक
- बेहतर स्वास्थ्य जनसांख्यिकीय लाभांश में सहयोग करेगा ⇒ अधिक लाभ

परन्तु यह कदम कुछ समस्याओं का सामना कर सकता है-

1. निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का विरोध
→ गुणवत्तापूर्ण सेवा हेतु प्रोत्साहन खत्म

2. सरकार के राजकोषीय व्यय पर अधिक भार ⇒ घटती राजकोषीय मुद्रा ⇒ आर्थिक संकट

3. आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं की अभी भी पिछड़े क्षेत्रों में पहुंच नहीं।

4. सरकारी अस्पतालों की प्रासंगिकता कम होगी ⇒ अतिरिक्त व्यय भार।

अतः राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को मूलाधिकार घोषित किया जा सकता है लेकिन राजकोषीय घाटे व उपरोक्त समस्याओं का समाधान पूर्वशर्त है। इसके लिए राज्य व केन्द्र दोनों को सभी हितधारकों (जनता, निजी अस्पताल, सिविल सोसायटी, विशेषज्ञ) के साथ एक बेहतर रणनीति बनानी होगी।

Q4. The PDS is the biggest food network program in the world yet India witnesses' food insecurity, malnutrition and hunger challenges. Discuss reasons, also Explain the reasons along with suitable suggestions. 250 words

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि. 2013 के तहत 67% जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति हेतु PDS प्रणाली को अपनाया गया जो 'उचित मूल्य की दुकानों' के माध्यम से चावल / गेहूँ / दाल आदि का क्रमशः 3/2/1 रु./kg पर गरीब जनता को वितरण करती है।

PDS खाद्य नेटवर्क विकास

परन्तु आने वाली समस्याएँ

① FPS की ओर से / → अपर्याप्त अवसंरचना
डिजिटलीकरण का अभाव

↳ FPS दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी & मिलावट

↳ बिचौलियों के साथ सांठगांठ

↳ समय पर नहीं खुलना

② FCI की ओर से → अनाजों का क्षमता से तीन गुना संग्रहण
↳ गुणवत्ता में कमी
सड़ा-गला अनाज

↳ खाद्य वितरण में अपारदर्शिता → खाद्य ट्रकों पर निगरानी अभाव → अनाज लिकेज

↳ FCI को फंडिंग की कमी → Extra Budgetary Resources का सहारा

③ संस्थागत घपलेबाजी
↳ घोस्ट कार्डधारकों की बड़ी संख्या
इन्क्लूजन-एक्सक्लूजन एरर → डाटा 2011 जनगणना आधारित (पुराना)

↳ खाद्य कीमतों का मुद्रास्फीति के साथ जुड़ाव नहीं → बाजार में महंगाई

अतः उपरोक्त समस्याओं को दूर करने हेतु कुछ निम्न कदम उठाने की जरूरत है-

⇒ डिजिटलीकरण का सहारा → FPS को ePoS से जोड़ना + आधार-मोबाइल लिंक
↳ FCI कों की जियो टैगिंग

Scanned with OKEN Scanner

⇒ **डेटा अद्यतनीकरण** → रजिस्ट्रार जनरल के वार्षिक डाटा का प्रयोग

↳ आधार - JAM का प्रयोग

⇒ **लिकेज पर रोक** → FCI गोदामों का PPP मॉडल → स्थानीय क्षेत्रों में स्थापित करना

↳ सबसे गरीब 21% (तेंदुलकर समिति) को भी 3/2/1 ₹/Kg पर उपलब्धता

अन्य को (APL) थोड़ा अधिक कीमत पर अनाज।

→ **शांता कुमार समिति** सिफारिशें लागू करना

↳ FPS को स्थानीय स्वशासन निकायों से प्रबंधन

↳ MSP का तार्किकीकरण ⇒ FCI पर दबाव कम हो

↳ प्राइस डेफिसिएंसी मार्केट जैसे तरीकों का प्रयोग

↳ FCI गोदामों की अवसंरचना को सुधारना

↳ बेहतर वेंटिलेशन व सुरक्षा

क्षेत्रों से दूर अवस्थिति।

इस प्रकार एक बेहतर लॉजिस्टिक्स सिस्टम व वितरण प्रणाली द्वारा ही SDG लक्ष्यों 1, 2, 2.4 की प्राप्ति संभव होगी।

Q5. In the context of "Sangathan se Samridhhi- Leaving no Rural Women Behind", discuss the potential of Self-Help Group (SHG) Movement in the women empowerment and poverty alleviation in present time. 250 words

समान पृष्ठभूमि व हितों वाले व्यक्तियों द्वारा साथ आकर आर्थिक-व्यावसायिक समूह का निर्माण करना, SHG का उदाहरण है। जैसे - लिज्जत पापड़, MAVIM आदि।

ES - 2020-21 के अनुसार देश के 90% SHGs में महिलाओं द्वारा संचालित है जो करोड़ों गरीब महिलाओं के जीवन का आधार बना है।

SHGs द्वारा महिला सशक्तिकरण

(1) गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता
तेजस्विनी

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा
उदा० - कुडुम्बश्री SHGs

(3) महिलाओं के उद्यमिता व औपचारिक कार्यप्रणाली से जुड़ाव

④ महिला आर्थिक व्यवस्था का औपचारिकरण
[NABARD के अनुसार 87% SHGs द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्ति]

⑤ सामाजिक सशक्तिकरण
↳ पितृसत्तात्मक सोच पर प्रहार
उदा॰ मिरलेवहन (KL) SHG द्वारा महिला सदस्यों को लिंग-समानता पर बल।
↳ पारिवारिक व्यवस्था में उचित स्थान प्राप्ति ⇒ सम्मान, बेहतर जीवन स्तर
↳ शिक्षा – स्वास्थ्य स्तर में बेहतरी

⑥ SDGs लक्ष्यपूर्ति → गरीबी, कुपोषण व महिला समानता की ओर।

परन्तु इसमें अभी भी कई समस्याएँ हैं :

⇒ अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा → वित्तीय समावेशन व साक्षरता अभाव
⇒ महिलाओं में जागरूकता अभाव → निरक्षरता अधिक
↳ ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्गमता

⇒ SHG आंदोलन में असमानता
↳ बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान व पहाड़ी-पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कमी

⇒ महिलाओं की खराब सामाजिक स्थिति
↳ केवल ~2% महिलाओं के संपत्ति नामकरण (RBI रिपोर्ट)
↳ ~53% महिलाएँ उपेक्षित (NHFS-V)

अतः जरूरत → SHGs को माइक्रो-फाइनेंसिंग से जोड़ना (SHG-बैंक लिंकेज स्कीम)
↳ बुनियादी अवसंरचना - डिजिटलीकरण व पंचायत क्षेत्रों के माध्यम से जागरूकता
↳ आर्थिक पैकेज → प्रदर्शन आधार पर (प्रियदर्शिनी स्कीम (GJ))
↳ बैंकों द्वारा दिए गए SHGs ऋण की समय पर ऑडिटिंग व टर्म शीट निगरानी।
इस प्रकार बेहतर जागरूकता व पहले से उपस्थित SHGs द्वारा चाहे सरकार-वित्तीय संस्थानों के साथ प्रयास किए जाएंगे तो SHGs 13 करोड़ महिलाओं से 30 करोड़ महिलाओं के सहायता करने में सहायक होंगे।

Q6. Indian is speeding towards integrating technology in Governance and goods and service delivery both. All this requires a worker (Civil Servant) who is not just committed but also has the competence to deliver on this evolving mandate. Comment 250 words

UNESCAP के अनुसार राज्य द्वारा बेहतर व समयबद्ध सेवाओं के प्रदायगी हेतु एक अच्छे शासन (गवर्नेंस) ढांचे की जरूरत होती है जो नवाचार व नवीन तकनीकी पर कार्य करता है।

भारत द्वारा सुशासन हेतु प्रयास

- नागरिक चार्टर की अनिवार्यता

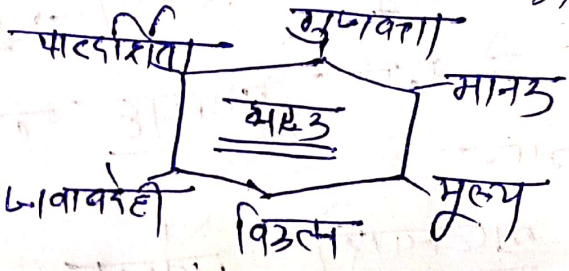

- लोकपाल - लोकायुक्त अधिनियम 2013
  - CVC, CBI आदि द्वारा सिविल सेवकों के कार्यों की वैधता जाँच
- सेवोत्तम मॉडल

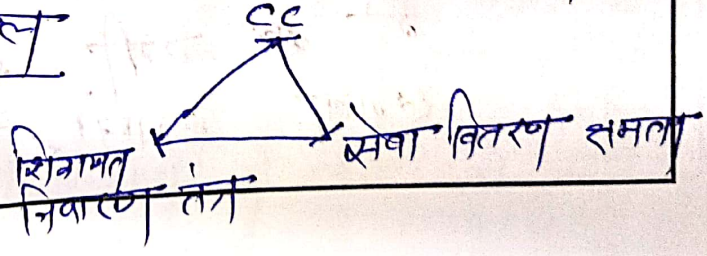

Scanned with OKEN Scanner

↳ विसल ब्लोअर एक्ट 2014 व RTI Act 2005 का पालन अनिवार्य

↳ ई-गवर्नेंस व ICT का बढ़ता प्रशासनिक संस्थागत प्रयोग → भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर।

परन्तु इसमें कई समस्याएं भी हैं

सिविल सेवकों की ओर से

↳ यथास्थितिवादी नजरिया → बदलाव नहीं
↳ सेवाओं के प्रति पूर्वाग्रह व गोपनीयता का भाव
↳ बढ़ता भ्रष्टाचारी स्वरूप
(उदा. पूजा सिंघल भ्रष्टाचार केस)
↳ भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अभाव के कारण करुणा, सहानुभूति जैसे मूल्यों की कमी → कार्यकुशल प्रबंधन क्षमता कमजोर।

बुनियादी समस्याएं।

↳ बढ़ता ट्रिपल डिवाइड { ग्रामीण - शहर, महिला - पुरुष, डिजिटल }

↳ राजनीति का अपराधीकरण → सहानुभूति व सामाजिक अनुबंधों का टूटना

↳ भौगोलिक प्रसार के कारण गुणवत्तापूर्ण - समयबद्ध सेवापूर्ति कठिन

↳ केन्द्र - राज्य संबंधों की कमजोरी।

↳ विवादों ने गवर्नेंस को कमजोर किया।

आगे की राह → सिविल सेवकों के उचित प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण जरूरत → मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम

↳ सेवाओं का स्थानीयकरण ⇒ सिविल सेवकों द्वारा जनता से संवाद ⇒ समस्या हल प्रभावी

↳ लेटरल एंट्री व कोड ऑफ कंडक्ट की कानूनी अनिवार्यता लागू करना जरूरी।

इस प्रकार एक बेहतर शासन संचालन हेतु सिविल सेवक उसके सेतु हैं जो सेवाओं को बेहतर बनाकर सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक न्याय के गांधीजी के सपने को साकार कर सकते हैं।

Q7. Same sex (Homosexual) Community has been one of the most marginalizes communities in Inda. Do you agree that the recognition of same sex marriage will help them to improve their situation. Give your argument in favor your opinion. 250words

NCRB डेटा के अनुसार LGBTQ+ समूह के खिलाफ 2018-2021 के बीच अपराधों में ~68% की वृद्धि हुई है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 हटाने के लक्ष्यों / उद्देश्यों की प्राप्ति में एक बड़ी बाधा परिलक्षित हो रही है।

LGBTQ+ के साथ समस्याएं

- सामाजिक कलंक के रूप में पहचान
- आर्थिक क्षेत्रों, रोजगार आदि में अयोग्य समझना → भीख मांगने को मजबूर
- समलैंगिकता के कारण आने वाली स्वास्थ्य समस्याएं
- सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जाना

समलैंगिक विवाह - क्या सही में लाभदायक

पक्ष → सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 हटाकर वैध किया जाना

↳ व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन (गरिमापूर्ण) जीने का अधिकार (अनु॰ 21)

↳ दो व्यक्तियों का निजी फैसला

↳ स्वास्थ्य लाभ
 ↳ मनोवैज्ञानिक संबल
 ↳ एक दूसरे का साथ → बेहतर आर्थिक साधन व जीवन स्तर।

↳ समाज की विचारधारा में बदलाव लाने हेतु शुरुआती कदम जरूरी।

विपक्ष
 ↳ सरकार द्वारा विरोध
 ↳ पारिवारिक ढाँचे को तोड़ने वाला कदम ⇒ भारतीय समाज में विवाह एक अनुबंध से ज्यादा सामाजिक मामला

↳ समलैंगिक सेक्सुअल संबंध स्वास्थ्य रूप में हानिकारक ⇒ HIV/AIDS व संक्रामक रोग संभव

↳ अप्राकृतिक संबंधों को मंजूरी देने वाला कार्य

अतः उपरोक्त वाद-विवाद के हल हेतु एक व्यापक व तार्किक विश्लेषण की जरूरत है -

① सरकार व अन्य हितधारकों के बीच वार्ता जरूरी

② सभी आशंकाओं जैसे (पारिवारिक ढाँचा संकट, स्वास्थ्य हानि) आदि पर डिस्कशन जरूरी है।

③ विशेषज्ञों व सामाजिक धार्मिक - LGBTQ+ संबंधी लोगों के बीच आम सहमति निकालना।

समग्रतः समलैंगिक विवाह अन्य देशों के परिणामों के अनुसार तो अनुमति होना चाहिए परन्तु भारतीय समाज के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन करके इसे लागू। मंजूरी देने की आवश्यकता है।

Scanned with OKEN Scanner